

**3** डीएसईजे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया**5** दिया ने कोनेरु हप्पी को हराकर जीता फिं महिला शतरंज विश्व कप का खिताब**8** कैसे करें दूध उत्पादन व्यवसायन्यूनतम
26मौसम अधिकतम
जम्मू 31

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

जम्मू तवी, बुधवार 30 जुलाई, 2025

मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये

पृष्ठ - 8

पहलगाम हमले के षड्यंत्रकारियों को ऑपरेशन सिंदूर का डर : लोकसभा में बोले मोदी

नई दिल्ली, 29 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम हमले के पीछे छिपे लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि आतंकवाद के आकाओं की नींद अब भी उड़ी हुई है।

लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर दो दिवसीय बहस का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले का उद्देश्य भारत में दंगे भड़काना था और देश की एकता ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया।

मैं यहाँ भारत का पक्ष रखने और उन लोगों को आईना दिखाने के लिए खड़ा हूँ जो इसे नहीं समझते। मैंने कहा था कि हम आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा करारा सबक सिखाएँ जो उनकी कल्पना से भी परे होगा। हमें अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और उन्हें जवाब देने की पूरी छूट दी गई थी।

“किसी भी देश ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा



उन्होंने कहा, सशस्त्र बलों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि आतंकवाद के आकाओं की नींद आज भी उड़ी हुई है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय कार्रवाई की भनक लग गई थी और उसने परमाणु हमले की धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ तो वह कुछ नहीं कर सका।

यह (पहलगाम हमला) भारत में

दंगे भड़काने की एक साजिश थी और देश की एकता ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैं इस संसद सत्र को विजयोत्सव कहता हूँ, तो इसका मतलब आतंक के मुख्यालयों को नष्ट करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस बात

पर भी खेद व्यक्त किया कि जहाँ देश को पूरी दुनिया का समर्थन मिला, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी देश के सैनिकों के पराक्रम के सामने खड़े नहीं हो सके। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर निचले सदन में दो दिवसीय बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोका। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा बार-बार पूछे जा रहे सवालों के बीच आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम की घोषणा क्यों की।

मोदी ने सदन को बताया कि 9 मई की रात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति (जेडी वेंस) ने मुझसे 3-4 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं सशस्त्र बलों के साथ बैठकों में व्यस्त था।

फोरेसिक बैलस्टिक और गवाहों ने पहलगाम हमलावरों की पहचान में मदद की : शाह

नई दिल्ली, 29 जुलाई। गवाहों की पहचान, श्रीनगर के दाचीगाम में मारे गए तीन आतंकवादियों से बरामद हथियारों की फोरेसिक बैलस्टिक जाँच के लिए आधी रात की उड़ान, और वैज्ञानिकों द्वारा सुबह-सुबह पुष्टि कि तीनों ने पहलगाम हमला किया था – यह सब 24 घंटे से भी कम समय में हुआ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन महादेव का विस्तृत व्यौरा दिया, जो सोमवार को तीनों आतंकवादियों के मारे जाने के साथ समाप्त हुआ।

शाह ने सदन को बताया कि भारतीय एजेंसियों के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि ये लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े पाकिस्तानी आतंकवादी बताया कि %ऑपरेशन महादेव% 22 मई को एक सुरक्षा योजना के तहत शुरू हुआ था, जो



22 अप्रैल को पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में हुए हमले में आतंकवादियों द्वारा 26 नागरिकों की हत्या के एक दिन बाद तैयार की गई थी।

23 अप्रैल को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में पहला निर्णय यह सुनिश्चित करना था कि क्रूर हत्यों को पाकिस्तान भागने की अनुमति न दी जाए।

शाह ने कहा कि यह सब तब शुरू हुआ जब 22 मई को डेटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को दाचीगाम के जंगल में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक मानवीय

□ **हुरियत आतंकवादियों का एक संगठन है, उनसे बात नहीं करेंगे**

खुफिया जानकारी मिली और एजेंसी ने सेना के साथ मिलकर उनके संकेतों को पकड़ने और उक्त जानकारी की पुष्टि करने के लिए स्वदेशी उपकरण तैनात किए।

उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को दाचीगाम में पाँच मानव संसाधन भेजे जाने और सेना की विशिष्ट 4 पैरा कमांडो इकाई द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर उन्हें घेरने के बाद सेंसर ने आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाया।

सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। मंत्री ने कहा कि जब उनके शव श्रीनगर लाए गए, तो चार लोगों ने

उनकी पहचान की।

शाह ने कहा, हम अभी भी संतुष्ट नहीं थे (कि क्या ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम हमला किया था)... और बताया कि सोमवार आधी रात के आसपास एक विशेष विमान श्रीनगर से उड़ान भरकर आतंकवादियों से जब्त की गई तीन राइफलों के साथ चंडीगढ़ उतरा।

उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरेसिक विज्ञान प्रयोगशाला (स्वस्) ने पहलगाम हमले स्थल से बरामद गोलीयों के खोलों का विश्लेषण पहले ही कर लिया था और वहाँ के विशेषज्ञों ने श्रीनगर से मंगवाई गई तीन राइफलों से पूरी रात और गोलीयाँ चलाई ताकि और गोले बनाए जा सकें।

आतंकवाद पर उपराज्यपाल के मंत्र का पालन कर रही पुलिस : डीजीपी



“आतंकवादियों का एक-एक करके सफाया किया जा रहा है

जम्मू तवी, 29 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा निर्धारित निर्देशों को न छुओ और दौषियों को न बख्शो के मूल सिद्धांत द्वारा निर्देशित न्याय के प्रति अपने पुलिस बल की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

प्रभात ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून धीरे-धीरे जमीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं और पॉइंट-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

उन्होंने यहाँ एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा, उपराज्यपाल का एक मंत्र (मार्गदर्शक सिद्धांत) है, निर्दोष को न छुओ और दौषियों को न बख्शो। यही जम्मू-कश्मीर पुलिस का कर्तव्य है। यही हमारा दृष्टिकोण है और यही हमारा निरंतर प्रयास है।

डीजीपी ने मुखिकल में फंसे लोगों तक पहुँचने के

प्रयासों में पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा, हम उन लोगों तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं जो उत्पीड़ित, व्यथित या पीड़ा में हैं। हम हर संभव तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनकी सभी समस्याओं के समाधान में हम उनके साथ खड़े हैं।

एक जनसमर्पक कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रभात ने इस बात पर जोर दिया कि यह मंत्र केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल के चरित्र और कार्यधर्माती को परिभाषित करता है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य उत्पीड़ितों के साथ खड़ा होना और उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करना है। पुलिस की बहुआयामी मॉर्गों पर प्रकाश डालते हुए, डीजीपी ने पुलिस बल के कर्तव्यों की तुलना विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने से की। उन्होंने कहा, मैं अक्सर अपनी टीम को ऊँचे लक्ष्य रखने के लिए कहता हूँ – जैसे भीतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतना, गणित में रणपूर्व पदक जीतना या किसी शीर्ष विश्वविद्यालय से पीएचडी हासिल करना। हमें हर भूमिका निभाने और वास्तविक बदलाव का माध्यम बनने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी ने उपराज्यपाल को ऑपरेशन महादेव के बारे में दी जानकारी



श्रीनगर, 29 जुलाई। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर क मांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी। उनके साथ 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत

श्रीवास्तव भी थे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को बधाई दी। चुनौतीपूर्ण दाचीगाम जंगल में अंजाम दिए गए इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन के परिणामस्वरूप जघन्य गणनाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों

का सफाया हो गया। उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दक्षिण कश्मीर से दाचीगाम के वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी था। इस क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की लगातार खबरें मिल रही थीं। हाल ही में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर विशेष टीमों को सक्रिय किया गया। इसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुफिया एजेंसियों की महत्वपूर्ण सहायता से एक संयुक्त अभियान शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया हो गया।

अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं कर सकता, तो भारत करेगा: राजनाथ

नई दिल्ली, 29 जुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो भारत पड़ोसी देश की मदद के लिए तैयार है क्योंकि भारतीय सेना सीमा पार भी आतंकवाद से लड़ने में सक्षम है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए, सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया – ऑपरेशन सिंदूर – रोक दिया गया है और अगर पाकिस्तान फिर से भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, तो इसे कभी भी फिर से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा, फ़भ्रात चाहता है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो... मैंने पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी



और आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत की मदद लें। भारत की सेनाएँ सीमा के इस पार और उस पार भी आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पहले ही इसका गदावां बन चुका है। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान भविष्य में कोई आतंकी घटना करता है, तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करेंगे।

आतंकवाद कभी कामयाब नहीं होगा: फारूक

श्रीनगर, 29 जुलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के दौषियों का खान्ता एक सबक है कि आतंकवाद कामयाब नहीं होगा।

अब्दुल्ला यहाँ एक समारोह से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा है और न ही मैं जानता हूँ कि वे कौन हैं। उन्हें केवल वही लोग पहचान सकते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। अगर वे मारे गए हैं, तो यह अच्छी बात है। उन्हें सबक मिल गया है कि आतंकवाद कभी कामयाब नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में घोषणा की कि पहलगाम नरसंहार को अंजाम देने वाले तीन आतंकवादियों को श्रीनगर के पास सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए, शाह ने कहा कि सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान सुलेमान उर्फ फैजल, अफगानी और ज़िबरान के रूप में हुई है।



उन्होंने कहा, सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का ए-श्रेणी का कमांडर था, अफगानी भी लश्कर-ए-तैयबा का ए-श्रेणी का आतंकवादी था और ज़िब्रान भी एक कुख्यात और वांछित आतंकवादी था। पहलगाम की बैसरन घाटी में हमारे नागरिकों की हत्या में शामिल सभी तीन आतंकवादियों का अब सफाया कर दिया गया है।

राहुल गांधी पाक गोलाबारी में अपने माता-पिता को खोने वाले 22 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएंगे

राजौर, 29 जुलाई। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन 22 बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पाकिस्तानी गोलाबारी में अपने एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद करी ने भी चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया, लेकिन कहा कि उनकी पार्टी पिछले नौ महीनों से सत्तारूढ़ दल के साथ समन्वय समिति के गठन का इंतजार कर रही है।



क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर राजौरी पहुँचें करी ने सोमवार देर रात संवाददाताओं से कहा कि पुंछ और राजौरी में (7 से 10 मई के बीच) पाकिस्तानी गोलाबारी में कई नागरिक हताहत हुए और संपत्तियों को नुकसान पहुँचा। विनाशकारी गोलाबारी के बाद राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने

हमें स्कूल जाने वाले उन बच्चों की सूची तैयार करने को कहा, जिन्होंने अपने माता-पिता में से एक या दोनों को खो दिया है, तदनुसार हमने उन्हें सूची सौंप दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास अकेले पुंछ जिले में ऐसे 22 बच्चों की सूची है और तीन दिवसीय दौरे के अंत में ऐसे और बच्चों को शामिल किया जा सकता है।

भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकी दौड़ों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी गोलाबारी और ड्रोन हमलों में 28 लोगों की मौत के अलावा अकेले पुंछ जिले में 13 नागरिकों की मौत हुई है।

1,490 तीर्थयात्रियों का 27वाँ जम्मू से घाटी के लिए रवाना

जम्मू, 29 जुलाई। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का 27वाँ जत्था आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 61 वाहनों के काफिले में कुल 1,490 तीर्थयात्री रवाना हुए। इस जत्थे में 1,262 पुरुष, 186 महिलाएँ और 42 साधु-साध्वियाँ शामिल हैं। कुल 327 तीर्थयात्री बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए जबकि 1,163 तीर्थयात्री पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए। इन शिविरों से तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। सुचारु और सुरक्षित यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

एनआईए ने श्रीनगर मुठभेड़ में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड के मारे जाने की जांच शुरू की



श्रीनगर, 29 जुलाई। पहलगाम आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड समेत दो आतंकवादियों के श्रीनगर के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की जांच एनआईए की एक टीम ने मंगलवार को शुरू की है। एनआईए की टीम मंगलवार तड़के तीनों आतंकवादियों के शवों की पहचान करने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि पहलगाम हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट फोन के दोबरा एक्टिव

होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन %महादेव% शुरू किया था। सेना के विशिष्ट पैरा कमांडो ने सोमवार को पहलगाम हमले के कथित मास्टरमाइंड सुलेमान उर्फ आसिफ को उसके दो साथियों के साथ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास हरवान झलाके के मुलानार में एक मुठभेड़ में मार गिराया था। कार्रवाई में मारे गए अन्य दो आतंकवादियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई। जिब्रान कथित तौर पर पिछले एक अवटूर में गगनगौर में सोनमर्ग सुरंग परिवर्तन पर हुए आतंकी हमले में शामिल था। इस हमले में एक डॉक्टर समेत सात लोग मारे गए थे अधिकारियों के अनुसार मारे गए आतंकवादियों के शव सोमवार देर रात मुठभेड़ स्थल से पीसीआर में लाए गए। एनआईए की टीम दो-तीन लोगों के समूहों में गवाहों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मारे गए आतंकवादियों में सुलेमान शाह भी शामिल है। सोमवार को मुठभेड़ स्थल से एक एम4 कार्बाइन राइफल, दो एफे राइफल और अन्य हथियार जब्त किए गए थे। खुफिया जानकारी मिलने के बाद से झलाके में आतंकवादियों के एक और समूह की मौजूदगी का पता चलने पर ऑपरेशन जारी है।



श्रीनगर, 29 जुलाई। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 से 31 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से जम्मू संभाग में तीव्र वर्षा और तेज हवाओं का अनुमान लगाया गया है। इस परामर्श में अचानक बाद, भूस्खलन और नदियों व नालों में जल स्तर बढ़ने की चेतावनी शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक पूरे केंद्र शासित प्रदेश में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और कई जगहों पर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में खासकर देर रात और सुबह के समय तेज बारिश और तेज हवाएँ चलने की संभावना है।

29 से 31 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना

29-30 जुलाई तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएँ, खास कर देर रात व सुबह के समय जम्मू और कश्मीर डिवीजन के कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 31 जुलाई से दो अगस्त तक हल्की बारिश के साथ गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इसी दौरान 3-5 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान जम्मू, रियासी, उधमपुर, कटुआ, राजौरी और सांबा जिलों में छिपटु स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है जिससे निचले इलाकों में जलभराव और संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवधान की चिंता बढ़ गई है। विभाग ने एक सलाह जारी कर कहा है कि पहाड़ी इलाकों में अचानक बाद, भूस्खलन और पथर गिरने की संभावना है और निवासियों और यात्रियों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों को नदी जलग्रहण क्षेत्रों की निगरानी करने और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है। 1 से 3 अगस्त तक मौसम सामान्य रूप से गर्म और आर्द्र रहने की उम्मीद है, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 4 से 6 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर होने का अनुमान है।

स्वतंत्रता दिवस-2025 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित, आवश्यक दिशा-निर्देश जारी



कटुआ/बसोहली 29 जुलाई। आगामी स्वतंत्रता दिवस-2025 की तैयारियों को लेकर एडीसी बसोहली फंज बभोत्रा की अध्यक्षता में एडीसी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए इस बैठक में एडीसी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बसोहली के प्रांगण में तथा बारिश होने की स्थिति में मल्टीपुर्पज हॉल जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। अधिकारी ने एई बिजली विभाग को 14 व 15 अगस्त को बिना किसी रुकावट के बिजली उपलब्ध करवाने तथा एईई जल शक्ति विभाग को कार्यक्रम स्थल पर पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। इसी प्रकार कार्यक्रम स्थल की सफाई की जिम्मेदारी ईओ म्यूनिसिपल कमेटी को सौंपी गई तथा बीएमओ को निर्देश दिए कि समारोह वाले दिन कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार किट तथा डॉक्टरों की टीम दवाइयों सहित तैनात रहेगी।



अगर हम यह कहें कि बनारस इतिहास, सभ्यता, मिथक और दंतकथाओं से भी पुराना है, तो यह गलत न होगा। वाराणसी को यह नाम यहां पर स्थित दो नदियों के कारण दिया गया, वरुण और असि।

इतिहास से भी पुराना बनारस

यह कहना शायद मिथ्या होगी कि विश्व में ऐसा कोई हिन्दू है, जो कि अरुप्रदेश में गंगा नदी के पवन तट पर बसे काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के बारे में नहीं जानता। वाराणसी के साथ ही साथ इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक है। अगर हम यह कहें कि बनारस इतिहास, सभ्यता, मिथक और दंतकथाओं से भी पुराना है, तो यह गलत न होगा। वाराणसी को यह नाम यहां पर स्थित दो नदियों के कारण दिया गया, वरुण और असि। यह दोनों नदियां काशी में गंगा में समाहित हो जाती हैं, जिस कारण से इसका नाम वाराणसी पड़ा। पुराणों के अनुसार काशी का निर्माण स्वयं भगवान शिव और देवी पार्वती के द्वारा किया गया था और इसीलिए इसे तीर्थों का तीर्थ समझा जाता है।

कहां ठहरें

होटल ताज गंगेज, होटल सिद्धार्थ, होटल गौतम वैड, होटल इंडिया, प्रीति गेस्ट हाउस, अग्निवा लाज, होटल मोती महल

कब जाएं

वैसे तो वाराणसी का मौसम हर समय सुहाना रहता है, लेकिन अगर आप वाराणसी जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च को होगा, जब आप बारिश या गर्मी की समस्या के बिना आराम से पूरा नगर घूम सकते हैं।



कैसे पहुंचें

रेल द्वारा: वाराणसी भारतीय रेलवे का एक मुख्य स्टेशन है। भारत के कई प्रमुख नगरों से वाराणसी के लिये सीधी ट्रेनें उपलब्ध रहती हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी से मात्र 16 किमी की दूरी पर स्थित मुगलसराय एक अन्य निकटतम प्रमुख स्टेशन है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है।

सड़क द्वारा: वाराणसी एनएच 2, एनएच 7 और एनएच 29 के द्वारा भारत के सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के सभी निकटतम प्रमुख नगरों से बस सेवा भी उपलब्ध रहती है। इसके अतिरिक्त आप निजी वाहन का प्रयोग भी कर सकते हैं।

वायुयान द्वारा: बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी का प्रमुख एयरपोर्ट है, जो कि वाराणसी से 18 किमी की दूरी पर स्थित है।



वर्गों देखें

चौरासी घाट: पवित्र गंगा नदी के तट को कुल चौरासी घाटों में विभाजित किया गया है, जिनमें स्नान करके शुद्ध होने के बाद ही श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाते हैं। वैसे तो लगभग सभी घाटों का कोई न कोई ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन कुछ घाट ऐसे भी हैं, जो कि धार्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे, काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे निकट दशाश्वमेध घाट के लिये माना जाता है कि यहां पर भगवान ब्रह्मा ने दस अश्वों की बलि दी थी। मणिकर्णिका घाट के लिये यह माना जाता है कि शिव के नृत्य करते समय यहीं पर उनके कान की मणि गिरी थी। हरिश्चन्द्र घाट के लिये यह किंवदंती है कि इस घाट पर स्थित तमशान पर ही राजा हरिश्चन्द्र काम किया करते थे। काशी का सबसे पहला घाट असि घाट है और सबसे आखिरी आदि केशव घाट जिसे वेदेश्वर घाट भी कहते हैं। गंगा दशहरा के दिन यहाँ एक शोभायात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि असि घाट से वेदेश्वर घाट तक जाती है।



काशी विश्वनाथ: बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थित भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगाना तो आज भी संभव नहीं है क्योंकि इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। वैसे तो इस मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त किया गया और कई बार इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया, लेकिन वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की मल्लिकार्जुन अहिल्याबाई होल्कर द्वारा सन् 1780 में करवाया गया था, जिसके बाद सन् 1835 में पंजाब के राजा महाराज रणजीत सिंह जी द्वारा इस मंदिर के मुंबदों पर करीब एक हजार किलोग्राम सोना लगावाया गया।

संकटमोचन मंदिर: काशी में असि नदी के किनारे रामभक्त हनुमान के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक संकटमोचन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा करवाया गया था। हनुमान जी को संकटमोचन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी संकटों को हरने वाला। इस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर कई मंदिर हैं, जिन्हें प्रसाद दिए बिना आपका मंदिर से बाहर जा पाना मुश्किल है।

भारत माता मंदिर: वाराणसी का भारत मंदिर भारत माता को समर्पित किया गया एक मंदिर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कैपस में स्थित इस मंदिर का निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा करवाया गया था, जिसका उद्घाटन सन् 1936 में महात्मा गांधी के हाथों से हुआ था। इस मंदिर में संगमरमर का बना भारत का एक नक्काशीदार मानचित्र है।

तुलसी मानस मंदिर: तुलसी मानस मंदिर का निर्माण वाराणसी के नागरिकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर मूलरूप से भगवान राम और उनके जीवनवचित्र को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर करवाया गया है, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर में एक रामचरितमानस का वर्णन करती हुई एक विद्वत प्रदरिनी का भी आयोजन किया जाता है।

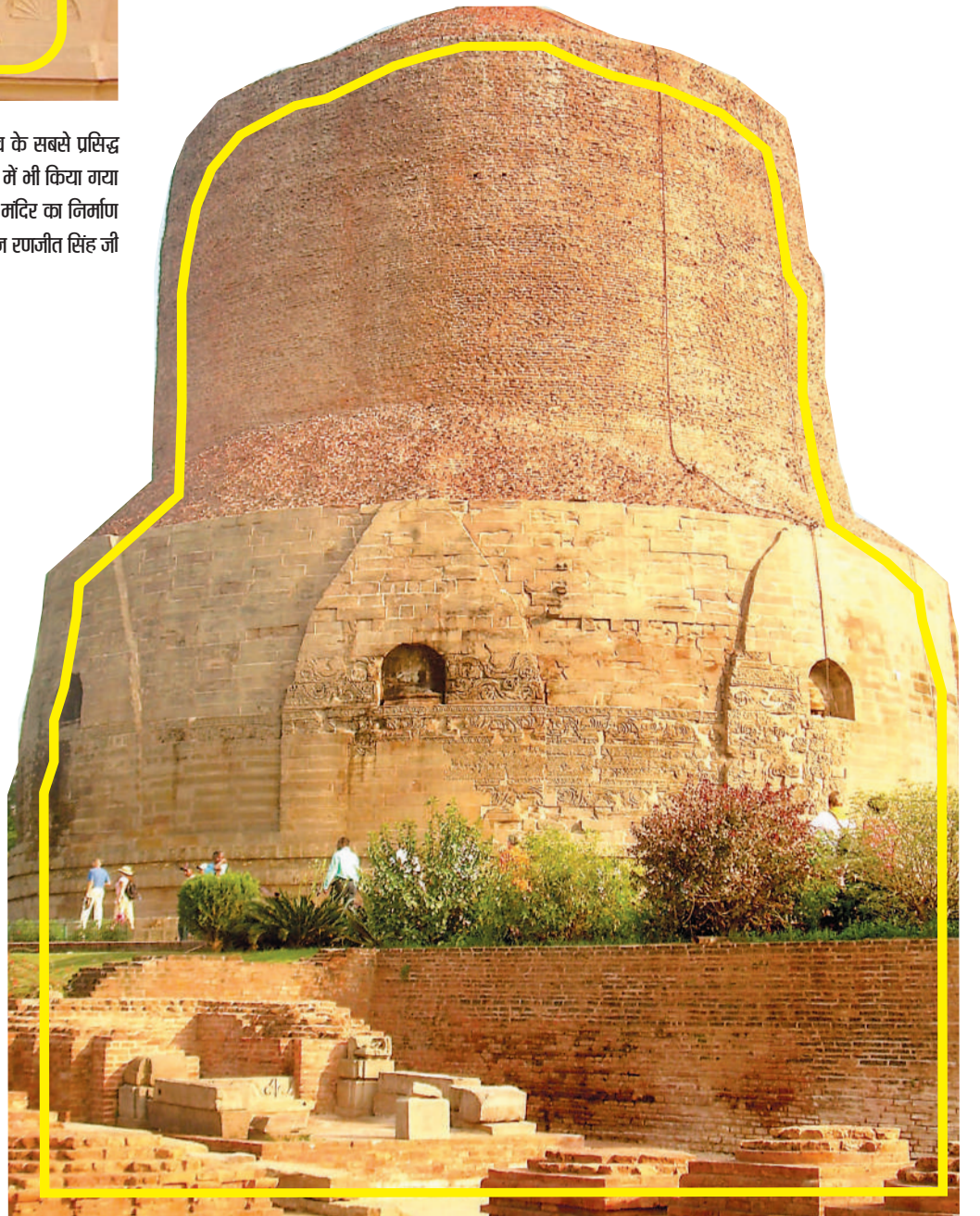
बिड़ला मंदिर: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में स्थित नए विश्वनाथ मंदिर को ही बिड़ला मंदिर कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा योजनाबद्ध किये गये इस मंदिर का निर्माण भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने बिड़ला परिवार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लोगों के लिये खुले हैं।

कालभैरव मंदिर: कालभैरव मंदिर मुख्य पोस्ट ऑफिस विश्वेश्वरगंज के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि कालभैरव काशी के रखवाले हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी बनारस में ठहर नहीं सकता है। इसीलिये उन्हें वाराणसी का कोतवाल भी कहते हैं।

सारनाथ: वाराणसी से करीब 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित सारनाथ भगवान बुद्ध को समर्पित है। सारनाथ बौद्ध धर्म का धार्मिक केन्द्र और चार तीर्थों में से एक है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही अपने पांच शिष्यों को अपने पहले उपदेश दिये थे। सारनाथ में प्रवेश करते ही सबसे पहला

महत्वपूर्ण स्थान चौखंडी स्तूप स्थित है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। धनेक स्तूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्तूप है और इसी के पास स्थित मूलगंध कुटी विहार भी स्थित है, जो कि एक बौद्ध मंदिर है। इसके अतिरिक्त सारनाथ में अन्य कई बौद्ध मंदिर भी हैं, जैसे कि चीनी मंदिर, तिब्बती मंदिर, जापानी मंदिर आदि। सारनाथ संग्रहालय भी सारनाथ के प्राचीन इतिहास का एक झरोखा देखने के लिये एक अच्छा स्थान है।

रामनगर: वाराणसी से मात्र 14 किमी की दूरी पर रामनगर स्थित है, जो कि रामनगर किले के लिये प्रसिद्ध है। गंगा नदी के किनारे इस किले का निर्माण सन् 1750 में वाराणसी के राजा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन यह आज अपने संग्रहालय के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें विटेज कार, शाही पालकी, तलवारें, बंदूकें आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी वाराणसी में कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा मंदिर, भारत कला भवन, काशी विद्यापीठ, दुर्गा मंदिर, जैन मंदिर आदि।



प्रधानमंत्री ने रखी पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला

तमिलनाडु, 29 जुलाई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई, 2025 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में आयोजित एक समारोह में कुडनकुलम यूनिट-3 और 4 (2×1000 मेगावाट) बिजली संयंत्र से बिजली की निकासी के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) द्वारा निर्मित किए जा रहे ट्रांसमिशन सिस्टम की आधारशिला रखी। अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजना के तहत पावरग्रिड कुडनकुलम ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना में 400 केवी डी/सी (काड) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (3 और 4) - तूतीकोरिन- ड्ब्लू जीआईएसपी एस ट्रांसमिशन



लाइन और तूतीकोरिन- II जीआईएस में दो 400 केवी जीआईएस लाइन टर्मिनल उपकरणों का निर्माण शामिल है। समारोह के दौरान श्री आर. एन. रवि, माननीय राज्यपाल, तमिलनाडु, श्री राममोहन नायडू किंजरापु, माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन,

माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री थंगम थेनारासु, माननीय कृषि मंत्री, तमिलनाडु, श्रीमती पी. गौता जीवन, माननीय समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण मंत्री, तमिलनाडु, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, माननीय सांसदतथा केंद्र एवं

राज्य सरकार और पावरग्रिड के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। यह परियोजना तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी सहित लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 गीगावाट स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करेगी, ताकि क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा माँगों

को पूरा किया जा सके। यह पारेषण अवसंरचना 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का भी समर्थन करती है, जो देश के एनर्जी ट्रांजिशन, सुरक्षा और हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

30 जून 2025 तक पावरग्रिड द्वारा 1,80,533 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों, 284 उप-केंद्रों और 5,66,831 एमवीए की ट्रांफॉर्मेशन क्षमता को कमीशन कर संचालित किया जा रहा है। नवीनतम तकनीकी उपकरणों व तकनीकों को अपनाने तथा स्वचालन और डिजिटल समाधानों के उन्नत उपयोग से पावरग्रिड 99.84न से अधिक की औसत ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता बनाए रखने में सक्षम रहा है।

डीएसईजे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया

जम्मू 29 जुलाई। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने परिवर्तनकारी भावना और शिक्षा प्रणाली पर इसके दूरगामी प्रभाव पर बात की। उन्होंने एनईपी 2020 द्वारा पिछली शिक्षा नीतियों की तुलना में लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में इस नीति की प्रासंगिकता पर जोर दिया और स्कूलों के समग्र विकास पर इसके ध्यान केंद्रित करने, बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन की ओर ध्यान आकर्षित किया।

संभागीय आयुक्त ने शिक्षकों और एससीईआरटी द्वारा विकसित नवीन शिक्षण-अधिगम सामग्री की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें एनईपी 2020 के तहत प्रचारित रचनात्मकता और शिक्षार्थी-केंद्रित िष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया।

अपने संबोधन में, संभागीय आयुक्त ने एनईपी 2020 की परिवर्तनकारी भावना और शिक्षा प्रणाली पर इसके दूरगामी प्रभाव पर बात की। उन्होंने एनईपी 2020 द्वारा पिछली शिक्षा नीतियों की तुलना में लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में इस नीति की प्रासंगिकता पर जोर दिया और स्कूलों के समग्र विकास पर इसके ध्यान केंद्रित करने, बच्चों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन की ओर ध्यान आकर्षित किया।

संभागीय आयुक्त ने शिक्षक समुदाय से परिवर्तन के वाहक बनने और एनईपी 2020 को उसकी वास्तविक भावना के अनुरूप लागू करके छात्रों के भविष्य को आकार देने का आग्रह किया। स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू नसीम जावेद चौधरी ने केंद्र

शासित प्रदेश में एनईपी 2020 के कार्यान्वयन का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन में सुधार, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और संसाधन साझाकरण एवं शैक्षणिक संवर्धन के लिए स्कूल परिसरों की स्थापना में विभाग के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता किट का वितरण था, जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जो विभाग द्वारा समानता और समावेशन पर निरंतर जोर देने को दर्शाता है। इस अवसर पर एससीईआरटी की संयुक्त निदेशक सिंधु कपूर, जेकेबीएस के अकादमिक निदेशक डॉ. सुधीर सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू अजीत शर्मा, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, डाइस्ट जम्मू, समग्र शिक्षा, जेकेयूटी के प्रतिनिधि, छान, जेडईओ, एचओआई, शिक्षक प्रशिक्षक और स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न विंग के अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति किया जागरूक



आरएस पुरा, 29 जुलाई (हि.स.)। किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ कृषि संबंधी जागरूक करने के मकसद से केशोलिक सोशल सर्विस सोसायटी जम्मू कश्मीर की तरफ से मंगलवार को अरनिया क्षेत्र के गांव तरेवा में एक दिवसीय किसान जागरूकता कैप का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में पंचायत की पूर्व सरपंच बलबीर कौर तथा गांधी ग्लोबल फैमिली के अध्यक्ष पदम श्री डॉ. एसपी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इसके अलावा कार्यक्रम में पूर्व

कृषि अधिकारी सरदार गुरदीप सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे जिन्होंने पंचायत के किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ धान की बेहतर पैदावार हासिल करने संबंधी किसानों को बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि कौन से समय पर कौन सी दवाई का छिड़काव फसल पर करना है तथा इस बात का भी किसानों को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बसमती की फसल को सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता काफी अधिक होती है।

‘समुदाय की सेवा और पार्टी को मज़बूत करने के लिए अथक प्रयास करेंगे’

जम्मू, 29 जुलाई (हि.स.)। बिश्नाह के डीडीसी धर्मिंदर कुमार ने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक भव्य और उत्साही सभा में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने पारंपरिक भगवा पगड़ी बाँधी जो सम्मान, जम्भिंदारी और उनके नेतृत्व में पार्टी के

विश्वास का प्रतीक है।समारोह में भाजपा उपाध्यक्ष एडवोकेट भी उपस्थित थे। रेखा महाजन, राज्य महासचिव संजीता डोगरा, बलदेव सिंह बिलावरिया और गोपाल महाजन, डीडीसी अध्यक्ष भारत भूषण (जम्मू) और लाल चंद (उधमपुर), विधायक डॉ. देविंदर कुमार मन्थाल, चंद्र प्रकाश गंगा, सुनील बरहाडान, एससी मोर्चा प्रभारी जगदीश भगत, पूर्ण विधायक और जिला अध्यक्ष नीलम लंगेह और अन्य गणमान्य व्यक्ति और पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे।

उपराज्यपाल ने बारामूला में कश्मीर की संस्कृति का जश्न मनाने वाले एक विशाल कार्यक्रम, कशूर रिवाज 2025 में भाग लिया

बारामूला 29 जुलाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बारामूला में कश्मीर की संर.ति का जश्न मनाने वाले एक विशाल कार्यक्रम, कशूर रिवाज 2025 में शामिल हुए।

अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने इतिहास रचने और विश्व रिकॉर्ड का खिताब हासिल करने के लिए बारामूला के 20,000 युवाओं को हार्दिक बधाई दी।

उपराज्यपाल ने कहा, लडीशाह और सुलेख के लिए एक साथ आकर आपने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि समाज के सभी वर्गों को अपनी विरासत से जुड़ने, अपनी संर.ति को अपनाने और अपने मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी।

उन्होंने इस सराहनीय प्रयास के लिए भारतीय सेना और



बारामूला जिला प्रशासन की भी सराहना की।

उपराज्यपाल ने कहा मैं हमारी सेना के समर्पण और प्रतिबद्धता को सलाम करता हूँ। वे न केवल राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र की जीवंत सांस्.तिक विरासत के संरक्षक के रूप में भी सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं और हमारे युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

विविधता में एकता भारत की

महान संर.ति की पहचान है। भारतीय सेना ने सामाजिक लाभ के लिए इस शक्ति का निरंतर उपयोग करने का प्रयास किया है, और युवाओं के लिए साहित्य, संगीत, कला और खेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के अवसर पैदा किए हैं।

उपराज्यपाल ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता

जीजीएचएसएस सांबा में पाँच दिवसीय एनईपी उत्सव-2025 का शुभारंभ

सांबा, 29 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पाँचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांबा में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ पाँच दिवसीय एनईपी उत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के समावेशन और सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त राजेश शर्मा उपस्थित रहे जिन्होंने एनईपी उत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। उनके साथ सहાયक आयुक्त राजस्व (एसीआर) अजय भारती, मुख्य शिक्षा अधिकारी सांबा केवल कृष्ण, जीएचएसएस सांबा की प्रधानाध्याय श्रीमती भावना अबरोल और भारती एयरटेल काउडेशन के दीपक ठाकुर भी मौजूद थे। अपने मुख्य भाषण में उपायुक्त राजेश शर्मा ने भारतीय शिक्षा में बदलाव लाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रांतिकारी दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और शिक्षा में समावेशिता, समानता और सुगमता के महत्व पर बल दिया।

मढ़ विधानसभा में विकास कार्यों का उद्घाटन



जम्मू , 29 जुलाई (हि.स.)। भाजपा जम्मू कश्मीर महामंत्री एवं जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने मढ़ विधानसभा के विधायक सुरिंदर कुमार भगत के साथ क्षेत्र के वार्ड 75 संग्रामपुर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस विकास कार्य में पुलिया के निर्माण कार्य को जम्मू नगर निगम की देखरेख में पूरा किया गया। इस अवसर पर भाजपा जम्मू कश्मीर महामंत्री एवं जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि यह विकास कार्य स्थानीय लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी और अब यह मांग पूरी हो गई है।

उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि मुझे उन विकास कार्यों के लोकार्पण का सौभाग्य भाजपा विधायक सुरेंद्र कुमार के

साथ मिल रहा है जिसकी मैंने योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जम्मू शहर के हर क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का प्रयास किया ताकि लोगों को उनके घर-द्वार पर विकास प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पुलिया के बनने से क्षेत्र की यातायात समस्या का समाधान होगा और स्थानीय लोगों की जीवनशैली में सुधार आएगा। बलोरिया ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार क्षेत्रीय विकास और जनहित के लिए निरंतर काम कर रही है।

आगामी दिनों में भी इस तरह के विकास कार्यों को तेज किया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर के हर हिस्से में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर हर सेवा प्रदान करना और मोदी सरकार विकास में विश्वास करती है न कि झूठे आश्वासन देती है। इस अवसर पर विधायक सुरिंदर कुमार भगत ने लोगों को आश्वासन दिया कि वार्ड में चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाएगी और जल्द ही अन्य चल रहे विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा।

अमृत योजना के तहत 594 करोड़ रुपये की लागत वाली जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास



सांबा 29 जुलाई। सांबा शहर में पेयजल की बेहतर पहुँच के उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के मिशन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने सांबा शहर में जल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखी।

सांबा शहर में जल आपूर्ति बढ़ाने की यह परियोजना अमृत 2.0 के तहत शुरू की जा रही है। इस परियोजना की

अनुमानित लागत 594 करोड़ रुपये है, जिसका लक्ष्य 530 कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करना है। यह योजना पूरी होने पर सभी 17 वार्डों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित होगा जिससे 30,000 से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। आधारशिला रखते हुए, राणा ने एक टिकाऊ और समतामूलक शहरी बुनियादी ढाँचे की दिशा में काम करने की उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार

की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा जलापूर्ति योजना से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने और विश्वसनीय एवं सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित होने की उम्मीद है। यह परियोजना केवल जल आपूर्ति में सुधार के बारे में नहीं है, बल्कि सांबा के प्रत्येक निवासी के लिए एक स्वस्थ और अधिक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के बारे में है। राणा ने अमृत 2.0 के तहत सतत शहरी विकास के सरकार के व्यापक लक्ष्य पर प्रकाश डाला। बाद में, जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीण सांबा में छह जलापूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन के तहत स्वी.त पाँच परियोजनाएँ और केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय बजट के तहत एक परियोजना, सांबा के कई गाँवों की वर्तमान और भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचागत पहल हैं।

संपादकीय रेबीज से बचाव

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुत्तों के काटने से रेबीज़ होने की घटनाओं से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने की खबर ने देश भर में, खासकर जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में, जहाँ आवारा कुत्तों का आतंक खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है, कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया होगा। समय की माँग है कि सभी हितधारक एकजुटता और समन्वय से काम करें ताकि रेबीज़ का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि संबंधित हितधारक जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में मलेरिया, टीबी, एचआईवी/एड्स, कोविड- 19 आदि की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियानों की तरह एक विशेष अभियान शुरू करें, क्योंकि यह बीमारी भी कम गंभीर और खतरनाक नहीं है।

इस संदर्भ में, कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन शामिल हैं, ने एक अंग्रेजी दैनिक के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार को बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया है क्योंकि इसमें रेबीज़ के प्रसार से संबंधित कुछ चिंताजनक और चिंताजनक आँकड़े और तथ्य शामिल थे। यद्यपि उपरोक्त रिपोर्ट में देश की राजधानी से संबंधित आंकड़े शामिल थे, लेकिन अन्य शहरों में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है और इसलिए अब सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी हैं कि वह इस रोकथाम योग्य बीमारी से निपटने के लिए उपाय बताए और लोगों की जान बचाए।

लोगों में विशेष रूप से उन लोगों के बीच आशा की किरण जगाते हुए जिन्हें विषम घंटों के दौरान बाहर काम करना पड़ता है और इस खतरे का अक्सर सामना करना पड़ता है, उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मुद्दे पर स्वत संज्ञान लेने के आदेश के साथ-साथ उपरोक्त समाचार रिपोर्ट को उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा है। जम्मू-कश्मीर का मामला लें तो रेबीज का खतरा बढ़ रहा है, खासकर श्रीनगर और जम्मू जैसे शहरी केंद्रों में, जहां आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी और सीमित जागरूकता महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। कुत्ते के काटने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन चिकित्सा सहायता में अंतराल, इस मुद्दे पर जागरूकता और नागरिक निकायों की सुस्ती रेबीज को एक मूक हत्यारे के रूप में कार्य करने की अनुमति दे रही है।

हालाँकि, रेबीज और कुत्ते के काटने से होने वाली मौतों की संख्या के बारे में तस्वीर स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि जम्मू-कश्मीर को भी जान बचाने और एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

बीबिपुर- एक गांव की कहानी, जो अब किताबों में पढ़ाई जाएगी

डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा का बीबिपुर गांव अब देशभर के छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। सीबीएसई बोर्ड ने इसकी सामाजिक क्रांति की कहानी कक्षा आठवीं के पाठ्यक्रम में शामिल की है। बेटी के नाम नेमप्लेट, लाडो सरोवर, खुले में शौच से मुक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रयासों ने इसे एक मॉडल गांव बनाया। पूर्व सरपंच प्रह्लाद डंगरा के नेतृत्व में यह गांव सोच और समाज दोनों बदलने में सफल रहा। बीबिपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक आशा की किरण और बदलाव का प्रतीक बन चुका है।

कभी एक सामान्य-सा गांव और आज देशभर के बच्चों के लिए प्रेरणा- हरियाणा का बीबिपुर गांव अब सिर्फ नवशे पर मौजूद एक बिंदु नहीं रहा, बल्कि सामाजिक बदलाव और विकास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। इतना ही नहीं, अब बीबिपुर गांव की यह अनूठी कहानी कक्षा आठवीं के छात्रों को भी पढ़ाई जाएगी।ICSE बोर्ड ने इसे अपने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। यह न केवल एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत के लिए एक संदेश भी है-परिवर्तन संभव है, अगर सोच बदले।

बदलाव की शुरुआत- एक बीज से विशाल वटवृक्षबीबिपुर गांव, हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। यह वही राय है, जहां

लिंगानुपात के असंतुलन, बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे दशकों तक चर्चा का विषय रहे हैं।

लेकिन इसी हरियाणा की मिट्टी से उभरा बीबिपुर, जिसने इन सभी धारणाओं को तोड़कर नई मिसाल कायम की। वर्ष 2010 में गांव के पूर्व सरपंच प्रह्लाद डंगरा ने एक ऐसी पहल की शुरुआत की, जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति में बदल गई। उनका सपना था — एक ऐसा गांव, जहां बेटी को सम्मान मिले, जल-संरक्षण हो, महिलाएं सशक्त हों, और समाज खुले में शौच से मुक्त हो।

नेमप्लेट पर लाडो का नामबीबिपुर गांव की सबसे चर्चित और क्रांतिकारी पहल रही- ऋबेटी के नाम नेमप्लेटऱ्। यह विचार बेहद सरल, मगर सामाजिक रूप से बेहद प्रभावशाली था। आज तक अधिकांश घरों की पहचान पुरुष सदस्य के नाम से होती थी, लेकिन बीबिपुर में घरों की पहचान बेटियों के नाम से शुरू हुई। इस पहल ने सिर्फ एक संकेत बदला नहीं, बल्कि सोच बदल दी। बेटियों को घर का गौरव मानने की दिशा में यह पहला साहसी कदम था। गांव के सैकड़ों घरों में बेटियों के नाम की तख्तियां लगीं और एक नई सामाजिक चेतना जागी।

लाडो सरोवर- बेटियों के नाम जल-स्त्रोतगांव में लाडो सरोवर की स्थापना सिर्फ जल संचयन का प्रयास नहीं था, बल्कि यह उस सोच का सम्मान था जो

बेटियों को प्रकृति के साथ जोड़ती है। यह एक प्रतीक बन गया- जीवन देने वाले जल और जीवन की जननी ‘बेटी’ के बीच के अटूट संबंध का। लाडो सरोवर ने गांव को पर्यावरणीय जागरूकता की राह पर भी अग्रसर किया और जल संरक्षण की प्रेरणा दी।

खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता की अलखबीबिपुर की सबसे बड़ी जीत उस समय मानी गई जब उसने खुले में शौच से पूरी तरह मुक्ति पा ली। शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी गई और इसके पीछे शर्म नहीं, स्वास्थ्य और गरिमा की भावना को रखा गया। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला, बच्चों को बीमारियों से राहत, और गांव को नई पहचान।

सोच बदली तो गांव बदलाप्रह्लाद डंगरा और उनकी टीम ने एक नारा दिया- सोच बदली तो गांव बदलाऱ्। यह नारा महज शब्दों की जुगलबंदी नहीं थी, यह हर बीबिपुरवासी के दिल की आवाज थी। पुरुषों की मानसिकता में बदलाव आया, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार मिला, बेटियों को शिक्षा और सम्मान मिला, और गांव की तस्वीर बदलने पंचायतें और जागरूकता कार्यक्रमगांव में महिला ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ, जहां महिलाएं खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव रखती थीं। यह लोकतंत्र का सचा रूप था, जिसमें आधी आबादी भी पूरी भागीदारी निभा रही थी।

शराबबंदी, दहेज, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर दर्ज किया गया।

अब किताबों में-- प्रेरणा का स्थायी स्थानआज जब सीबीएसई बोर्ड ने बीबिपुर गांव की इस कहानी को कक्षा आठवीं की किताब में शामिल किया है, तो यह किसी पुरस्कार से कम नहीं। यह कहानी अब देशभर के लाखों छात्र-छात्राओं को पढ़ाई जाएगी। वे जानेंगे कि बदलाव के लिए बड़े-बड़े भाषण या योजनाएं जरूरी नहीं होतीं — बस एक व्यक्ति की दृढ़ इछा शक्ति और सामाजिक भागीदारी ही काफी होती है। यह न केवल छात्रों को सामाजिक विज्ञान का पाठ

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता : एक क्रांतिकारी कदम



केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे कराधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किये गये किसी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी क्षेत्र या छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखकर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की अपनी नीति को बरकरार रखा है। वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैनुफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से

25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस करार के साथ, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नियोजित दृष्टिकोण, वैश्विक प्रतिष्ठा और साहसिक निर्णय साथ चलते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश भी वैश्विक मंच पर निर्णायक बन सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच सीईटीए के अस्तित्व में आने से एक नये आर्थिक सूर्य का उदय हुआ है, जिससे रोजगार सहित अनेक उन्नत राष्ट्र-निर्माण के अवसर सृजित होंगे। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने के अपने संकल्प में नये पंखों को जोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के व्यापारिक दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था, लेकिन अतीत की उन बड़ी भूलों को सुधारा जा रहा है, जो नये

भारत-विकसित भारत का आधार है।

मोदी के मेड इन इंडिया संकल्प की दृष्टि से यह डील बेहद अहम है। इससे करीब 99 प्रतिशत निर्यात यानी यहां से ब्रिटेन जाने वाली चीजों पर टैरिफ से राहत मिलेगी। इसी तरह ब्रिटेन से आनी वाली चीजें भारत में सस्ती मिल सकेंगी। जिससे आम लोगों को अधिक गुणवत्ता वाला सामान सस्ते में सुलभ होगा और जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। डील से एक बड़ा फायदा होगा टेक्सटाइल्स, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को। इनसे मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.8 प्रतिशत है, जबकि चीन की 28.8 प्रतिशत। इसी तरह, देश की जीडीपी में मैनुफैक्चरिंग का योगदान 17 प्रतिशत है और सरकार इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है। इस तरह की डील से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होगा। कृषि सेक्टर को भी उन्नत बनाने एवं अधिक उत्पाद की दृष्टि से व्यापक फायदा होगा। इसके लिए इस समय भारत की बातचीत अमेरिका से भी चल रही है। लेकिन वहां कृषि और डेयरी प्रॉडक्ट्स को लेकर रस्साकशी है। अमेरिका इन दोनों क्षेत्रों में खुली छूट चाहता है, जबकि अपने लोगों के हितों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार होने से भारत के कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी क्षेत्र या छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखकर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की अपनी नीति को बरकरार रखा है। वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैनुफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा।

क्रांतिकारी सुधारों, नवाचार, तकनीक, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आर्थिक सूरज के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है और भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं नागरिक हितों तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अब अनेक सुविधाएं मिलेगी।

साल 2014 के बाद से भारत ने मॉरिशस, यूएई,

पढ़ाएगी, बल्कि समाज विज्ञान का असली अर्थ भी समझाएगी। शिक्षा से बदलाव की वापसीबीबिपुर की कहानी बच्चों को यह सिखाएगी कि गांव का विकास केवल सड़क या इमारतों से नहीं होता, बल्कि विचारों से होता है। यह पाठ छात्रों में सामाजिक नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच का बीज बोएगा। और यही तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है- सोच में परिवर्तन।

क्या बाकी गांव सीखेंगे? बीबिपुर एक मॉडल है, परंतु यह अकेला नहीं होना चाहिए। आज देश के हजारों गांव सामाजिक कुरीतियों से जुझ रहे हैं। कहीं बेटियों की भ्रूण हत्या हो रही है, कहीं खुले में शौच आज भी आम है, कहीं शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। ऐसे में बीबिपुर की कहानी एक आदर्श प्रस्तुत करती है — अगर वे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? सरकारों को चाहिए कि ऐसे उदाहरणों को पाठ्यक्रम से आगे ले जाकर नीति-निर्माण का आधार बनाएं। पंचायतों को प्रशिक्षित किया जाए, महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिले, और गांवों में मूलभूत बदलाव लाने के लिए ऐसे मॉडल को स्थानीय भाषाओं में प्रचारित किया जाए।

बीबिपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक विचार हैबीबिपुर की सफलता की असली कुंजी सहभागिता, जागरूकता और नेतृत्व है। यह गांव बताता है कि असल क्रांति हथियारों से नहीं, सोच की धार से आती है। यह कहानी यह भी बताती है कि कोई गांव छोटा नहीं होता, अगर उसकी सोच बड़ी हो। आज जब बीबिपुर की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, तो वह सिर्फ एक पाठ नहीं होगी, बल्कि सपनों के बीज बोने वाली प्रेरणा होगी। हो सकता है, किसी बच्चे के मन में यह कहानी एक चिंगारी जला दे, जो कल किसी और गांव को रोशन कर दे। बीबिपुर अब सिर्फ एक स्थान नहीं, एक आंदोलन, एक प्रेरणा और एक जीवित पाठशाला है- जहां से देश को नई दिशा मिलेगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

- ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सामार : प्रभासाक्षी

देहात संदेश

देश का औद्योगिक उत्पादन जून में 10 महीने के निचले स्तर 1.5 फीसदी पर

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई है। खनन और बिजली क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जून में सुस्त पड़कर 10 माह के निचले स्तर 1.5 फीसदी पर आ गई है। औद्योगिक उत्पादन इससे पिछले साल जून में 4.9 फीसदी की दर से बढ़ा था। मानसून के जल्दी आने से खनन और बिजली क्षेत्र की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने मई महीने के जारी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर के आंकड़े को भी संशोधित कर 1.9 फीसदी कर दिया है, जबकि इससे पहले इसके 1.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त, 2024 के बाद औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि सबसे कम है, उस समय इसकी वृद्धि दर स्थिर रही थी। एनएसओ के जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि जून में मामूली रूप से बढ़कर 3.9 फीसदी रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 3.5 फीसदी थी। खनन क्षेत्र के उत्पादन में 8.7 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि एक साल पहले इसमें 10.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी तरह बिजली क्षेत्र के उत्पादन में जून में 2.6 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसमें 8.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई थी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में दो फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसमें 5.4 फीसदी की वृद्धि हुई थी।

आयकर विभाग को तकनीकी गड़बड़ी के चलते खारिज ई-रिटन की प्रोसेसिंग के लिए समय मिला

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आयकर रिफंड के दावों को प्रोसेसिंग में त्रुटि पूर्ण तरीके से अमान्य किये गये मामलों में प्रोसेसिंग प्रक्रिया के लिए समय सीमा में छूट प्रदान की है। यह निर्णय विगत में दाखिल कुछ मामलों में प्रोसेसिंग के दौरान तकनीकी दिक्कतों की शिकायत मिलने के बाद किया गया है। बोर्ड में इस संबंध में परिपत्र संख्या -10/2025 जारी किया है?। सीबीडीटी ने जारी परिपत्र में कहा है कि उसे आयकर के सीपीसी बेगलुरु को विभिन्न तकनीकी कर्म से कुछ रिटर्न को त्रुटि पूर्ण तरीके से अमान्य किए जाने के संबंध में शिकायतें मिलने की सूचना मिली थी। परिपत्र में कहा गया है कि ऐसे रिटर्न के संबंध में प्रोसेसिंग की समय सीमा नियमानुसार बढ़ा दी गयी है और संबंधित करदाताओं को अब उनके रिटर्न के बारे में सूचना 31 मार्च 2026 तक भेज दी जाएगी। सीबीडीटी ने कहा है कि ऐसे मामलों में ब्याज सहित रिफंड की कार्यवाही की जाएगी लेकिन इसके लिए संबंधित मामलों में पेन और आधार का लिंक होना जरूरी है।

नये डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल पर एमएसएमई के 98,995 ऋण आवेदन मंजूर

नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में बताया कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई क्षेत्र) की इकाइयों की सुविधा के लिए लागू नये डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में पहली अप्रैल से 15 जुलाई के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा कुल 98,995 ऋण आवेदन मंजूर किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को यह जानकारी देते हुए कहा कि नये डिजिटल क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के माध्यम से बैंक ऋण पर निर्णय एक दिन के भीतर लिया जाता है, जिससे मैनुअल तरीकों की तुलना में कार्य निष्पादन समय (टीपीटी) में काफी कमी आयी है। इस मॉडल के उपयोग से एमएसएमई इकाइयों को ऑनलाइन मोड में कहीं से भी आवेदन प्रस्तुत करने की आसानी, कागजी कार्रवाई और शाखा में जाने की आवश्यकता कम होने, डिजिटल मोड के माध्यम से तत्काल मंजूरी, ठेस सूचना और कारोबार के आधार पर ऋण संबंधी निर्णय जैसे लाभ भी रहे हैं। मंत्री ने बताया कि नए मॉडल के तहत ऋण संबंधी निर्णय अग्रावृत्तों के वस्तुनिष्ठ आंकड़ों तथा कारोबार के व्यवहार और आवेदक के कर्ज संबंधी इतिहास पर आधारित होता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए नये डिजिटल ऋण मूल्यांकन मॉडल की घोषणा की गई थी।

गेहूँ नरम, चावल महँगा, गुड़-चीनी, दालें महँगी, खाद्य तेलों में घटबढ़

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिनस बाजारों में चावल के दाम बढ़ गये जबकि गेहूँ में गिरावट रही। गुड़ और चीनी के भाव भी चढ़े। दालों के दाम बढ़े हैं जबकि खाद्य तेलों में उतार चढ़ाव देखा गया। विदेशों में मलेशिया के बुरुसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अक्टूबर वायदा 34 रिगिट गिफर 4,239 रिगिट प्रति टन पर आ गया। अमेरिका में सोया तेल वायदा में 0.03 प्रतिशत की तेजी रही और यह 56.01 डॉलर के भाव बोला गया। घरेलू थोक जिनस बाजारों में चावल की औसत कीमत 84 रुपये बढ़कर 3,813.84 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी। वहीं, गेहूँ 13 रुपये की नरमी के साथ 2,23.83 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटा 18 रुपये सस्ता होकर 3,822.27 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। सरसों तेल 66 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया। मूँगफली तेल औसतन 34 रुपये प्रति क्विंटल महँगा हुआ। सोया तेल 80 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ। वनस्पति करीब 30 रुपये प्रति क्विंटल महँगा हुआ। सूरजमुखी तेल में 53 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गयी। पाम ऑयल के दाम लगाभ स्थिर रहे। दाल-दलहनॉ में तेजी रही। दलहन बाजार में मसूर दाल में औसतन 95 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज की गयी।

ई-श्रम पोर्टल पर 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में ई-श्रम पोर्टल पर 22 जुलाई, 2025 तक 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएनए) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों (एनडीयूइव्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की थी। उन्होंने सदन को बताया कि अब तक विभिन्न केन्द्रीय



ताकि ईश्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा अथवा कोशल विकास कार्यक्रमों के लाभ और पहुंच प्रदान की जा सके, जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत देशभर में 01 जुलाई, 2025 तक लगभग 10.33 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। ये योजना मई 2016 में देशभर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी।केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह

जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करना था, जो जनवरी 2022 में हासिल कर लिया गया। सुरेश गोपी ने सदन को बताया कि इसके बाद सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60

साभार : अशोक कुमार मुनडेतिथ्या

राजस्थान को मनरेगा में केंद्र सरकार ने दिए 4384 करोड़ रुपये-शिवराज सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि भवन में मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव शैलेश सिंह, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित दोनों केंद्रीय मंत्रालयों और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की ओर से महات्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी



रुपये यानी कुल मिलाकर 4384 करोड़ रुपये को राशि राजस्थान को इसी वित्तीय वर्ष में दी गई है। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने केंद्रीय मंत्री चौहान को राज्य की ओर से धन्यवाद दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

सर्पाफा बाजार में सपाट स्तर पर कारोबार, सोना-चांदी के भाव में बदलाव नहीं

एजेंसी

नई दिल्ली। लगातार पांच दिनों की गिरावट के बाद आज घरेलू सर्राफा बाजार सपाट स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज के कारोबार में सोना और चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में बदलाव नहीं होने के कारण आज भी देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 99,920 रुपये से लेकर 1,00,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज सोमवार के भाव 91,590 रुपये से लेकर 91,740 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच ही बिक रहा है।



में 24 कैरेट सोना 99,920 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 91,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 99,970 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,640 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के

स्टॉक मार्केट में मोनार्क सर्वेयर्स की जोरदार एंट्री, लिस्टिंग के बाद बना बिकवाली का दबाव

एजेंसी

नई दिल्ली। सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री करके अपने



कंसल्टेंट्स का 93.75 करोड़ रुपये का आईपीओ 22 से 24 जुलाई के बीच सभ्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जबदस्त रिसर्च मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 250.65 गुना सभ्सक्राइब हो गया था। इनमें

क़ालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (व्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 179.01 गुना सभ्सक्राइब हुआ था।



इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 317.05 गुना सभ्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 263.01 गुना सभ्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 37.50

लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनों खरीदने, वकिंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 8.59 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 30.01 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 34.83 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के राजस्व में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। 2022-23 में कंपनी को 11.68 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो 2023-24 में बढ़ कर 42.78 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 51.10 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि की राह पर अग्रसर: वित्त मंत्रालय

मुद्रास्फीति लक्ष्य के दायरे में रहने और मानसून में अच्छी प्रगति के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत



मजबूती के साथ वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में प्रवेश की है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर तनाव और नहीं बढ़ा है, लेकिन वैश्विक नरमी, विशेष रूप से अमेरिका में कमजोर आर्थिक वृद्धि दर भारतीय निर्यात की मांग को और कम कर

हैं।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री ने बताया कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की। सरकार ने अक्टूबर 2023 में लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं

में।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री ने बताया कि पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की। सरकार ने अक्टूबर 2023 में लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये कर दिया। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं

जम्मू, बुधवार 30 जुलाई, 2025

एजेंसी

नई दिल्ली। देश ने औद्योगिक एवं संस्थागत विकास में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आधारभूत योगदान को याद किया। भारी उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उल्लेख्य में एक विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्यमंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने अपने संबोधन में संविधान सभा के सदस्य के रूप में और बाद में केंद्रीय उद्योग एवं अपूर्णित मंत्री के रूप में डॉ. मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। वर्मा ने देश के औद्योगिक और संस्थागत विकास में डॉ. मुखर्जी के मूलभूत योगदान को भी रेखांकित किया। उन्होंने अपने संबोधन में उन्हें

एक प्रखर विद्वान, राजनेता, निर्भीक सांसद और शिक्षाविद् के रूप में याद किया, जिनका जीवन साहस, दृढ़ विश्वास और एक राष्ट्र, एक संविधान में अटूट विश्वास का एक कालातीत प्रतीक बना हुआ है। इस अवसर पर डॉ. मुखर्जी विरासत और योगदान को श्रद्धांजलि स्वरूप एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी। यह फिल्म उनके जीवन की दुर्लभ झलकियाँ और प्रभावशाली गणन के जरिए उन्हें एक राष्ट्र निर्माता और दूरदर्शी नेता के रूप में प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखने में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है। इससे पहले उद्घाटन भाषण में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने भारत के औद्योगिक विकास के लिए डॉ. मुखर्जी के विजन पर बल दिया, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार बनाने पर उनके जोर को रेखांकित किया।

भारत में पिछले 6 वित्तीय वर्षों में 12,000 लाख करोड़ रुपये के 65,000 करोड़ से अधिक हुए डिजिटल लेनदेन

(एनपीसीआई), फिनटेक, बैंकों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें टियर-2 और टियर-3 शहर भी शामिल हैं। वित्त



राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक और सवाल के जवाब में कहा कि 1 अप्रैल से 15 जुलाई, 2025 के बीच नए क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की ओर से कुल 98,995 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ऋण आवेदन मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए डिजिटल क्रेडिट

डॉलर के मुकाबले 13 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

एजेंसी

नई दिल्ली। स्टॉक मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों की जमकर बिकवाली के कारण आज रुपया डॉलर की तुलना में गिरावट के साथ बंद हुआ। मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 13 पैसे फिसल कर 86.66 (अंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय मुद्रा 86.53 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की मजबूती के साथ 86.47 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। दिन के कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए डॉलर की आवक बढ़ने पर रुपया 13 पैसे की मजबूती के साथ 86.40 के स्तर तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों बिकवाली शुरू करके डॉलर की निकासी शुरू कर दी। ऐसा होने पर मुद्रा बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई, जिससे रुपये पर भी दबाव बढ़ गया। डॉलर की मांग तेज होने पर रुपया ऊपरी स्तर से 27 पैसे फिसल कर 14 पैसे की कमजोरी के साथ 86.67 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में मुद्रा बाजार में डॉलर की आवक बढ़ने पर रुपये की स्थिति में मामूली सुधार हुआ और भारतीय मुद्रा ने 86.66 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का मानना ​​है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार से अपने पैसे की निकासी के साथ ही वैश्विक बाजार में जारी उथल पुथल ने आज भारतीय मुद्रा को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई।

एम एंड बी इंजीनियरिंग का आईपीओ 30 जुलाई को

एजेंसी

अहमदाबाद। एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड का प्राथमिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) 30 जुलाई को खुलेगा और इसमें 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले शेयर के आवेदन मूल्य का दायरा 366 से 385 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने एक प्रेस वित्ति में कहा है कि उसका आईपीओ बुधवार, 30 जुलाई को खुलेगा और शुक्रवार 01 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक मंगलवार को बोली लगा सकेंगे। छोटे निवेशक न्यूनतम 38 या उसकी गुणक संख्या में शेयरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह



निर्गम प्रस्तावित 650 करोड़ रुपये तक का है, जिसमें 275 करोड़ रुपये मूल्य तक के नये इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और वर्तमान शेयरधारक शेयर बाजार में 375 करोड़ रुपये मूल्य तक के शेयर बिक्री के प्रस्ताव (ओफरएस) के तहत बेचने वाले हैं। कंपनी ने आईपीओ के पैसे से उपकरण और मशीनरी की खरीद, भवन तथा सौर रूपटॉप गिड के निर्माण और वाहनों की खरीद का योजना बना रखी है। इसके अलावा वह इस पैसे से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उन्नयन तथा पुराने ऋणों के पूर्व-भुगतान करेगी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य पूरे करेगी।

8 देहात संदेश

कैसे करें दूध उत्पादन व्यवसाय

सी एम शर्मा

दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग छेटे व बड़े स्तर दोनों पर सबसे ज्यादा विस्तार में फैला हुआ व्यवसाय है। दूध उत्पादन व्यवसाय व्यावसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों की कुल दूध उत्पादन में मदद करता है और उसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, भारत में कई वर्षों से डेयरी व्यवसाय या दूध उत्पादन ने आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल दूध उत्पादन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी की है और बहुत से गरीब किसानों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया है। यदि किसी के पास दूध उत्पादन का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी है तो इस दूध उत्पादन व्यवसाय को किसी भी क्षेत्र में आसानी से स्थापित किया जा सकता है।

छोटे स्तर पर दूध देने वाले पशुओं को बढ़ावा देने की भारत में सामान्य प्रथा है। कुछ किसान आधुनिक दूध उत्पादन (डेयरी व्यवसाय) तरीकों को नहीं जानते हैं। डेयरी व्यवसाय तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण कभी-कभी वे लाभ प्राप्त करने के स्थान पर निवेश की लागत को भी खो देते हैं। अधिकतम दूध उत्पादन और डेयरी व्यवसाय से लाभ को सुनिश्चित करने के साथ ही सभी चीजों का योजना के अनुसार प्रबंध करने के लिए उचित व्यवसाय योजना के साथ प्रभावी रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है।

► ***डेयरी व्यवसाय या दूध उत्पादन व्यवसाय क्या है?***

दूध उत्पादन भारत में सबसे सामान्य व्यवसाय है, जिसमें दूध का उत्पादन अधिकतम करने के लिए किसान दूध के उत्पादन के लिए गाय और भैंसों का प्रबंध उपयोग, कच्चे वह उत्पादन छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर। इस कारोबार में पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी सहित उचित लिए आवश्यक दवा, उचित भोजन, दूध देने वाले उपकरणों का समुचित उपयोग, कच्चे का प्रबंधन आदि कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं, हालांकि यह अन्य व्यवसायों की तुलना में शुरू करने में आसान है। कुछ दुग्ध उत्पादक स्वयं दूध उत्पादन करके उसे वितरित करते हैं, हालांकि उनमें से कुछ डेरी की प्रक्रिया के लिए कंपनियों को दूध की आपूर्ति करते हैं।

मुख्य सचिव ने ‘संपूर्णता सम्मान’ पुरस्कारों की तैयारियों की समीक्षा की

श्रीनगर 26 जुलाई।मुख्य सचिव अटल ड्रुहू ने आगामी केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय ‘संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह’ की तैयारियों की समीक्षा हेतु योजना विभाग की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

यह कार्यक्रम उन जिलों और प्रखंडों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है जिन्होंने राष्ट्रवापी संपूर्णता अभियान के तहत संतुष्टि प्राप्त करने में असाधारण प्रदर्शन किया है।

बैठक में योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, महानिदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशक, योजना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकांक्षी जिलों के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और लोक स्तर के अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किए जा रहे जिला स्तरीय सम्मान समारोहों की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने उपायुक्तों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनकी प्रगति की समीक्षा की और उन्हें

डेरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान कारोबार है हालांकि इसके लिए कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और इसे बड़े स्तर का व्यवसाय बनाने के लिए कुछ तकनीकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कुछ शिक्षित लोग इसे पूरी योजना के साथ डेरी विज्ञान, कृषि, इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में डिग्री लेने के द्वारा करते हैं। एक सफल दुग्ध उत्पादक बनने के लिए किसी को भी इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव रखने की आवश्यकता है। एक दुग्ध उत्पादक की जिम्मेदारियां डेरी व्यवसाय के आकार और कार्यों के अनुसार अलग-अलग होती हैं। छोटे दुग्ध उत्पादकों को बड़े प्रयासों की आवश्यकता होती है और इनका विकास भी धीरे-धीरे होता है, वहीं बड़े उत्पादकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन इसकी प्रवृत्ति व्यक्ति और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने की होती है।

चाहे आप इस व्यापार को छोटे स्तर पर करें या बड़े स्तर पर, दोनों को ही चारे का प्रबंधन, खिलाने, दुहने (दूध निकालने), प्रसंस्करण आदि की आवश्यकता होती है। एक दुग्ध उत्पादक को पशुओं के स्वास्थ्य के प्रबंधन और अन्य चिकित्सकीय स्थितियों के लिए पशु चिकित्सकों के साथ ही पोषण विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होती है। उन्हें दूध के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए घुमावदार (रोटरी) और समानांतर दूध निकालने की आधुनिक प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए, जो किसानों को बड़ी संख्या में कम समय में गायों और भैंसों का दूध निकालने में मदद करती है। वहीं दूध निकालने के पुराने तरीके के लिए अधिक पर्यवेक्षण और प्रयासों सहित अधिक मेहनत की जरूरत होती है। यदि सभी चीजों का सही तरीके से प्रबंध किया जाये तो किसान दिन में तीन बार दूध प्राप्त कर सकते हैं।

► ***दुग्ध उत्पादन का विस्तार***

दुग्ध उत्पादन बड़े स्तर का व्यवसाय है और यह वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले दो वर्षों में 8–9ब वृद्धि हुई है। डेरी क्षेत्र भारत के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यह बड़े स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था में भागीदारी करता है। यह कारोबारी क्षेत्र है, जो बहुत से अशिक्षित और शिक्षित बेरोजगार लोगों को लाभदायक रोजगार

प्रदान करता है। यह बड़े व्यापारियों की अनुपूरक आय का स्रोत है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सी पूंजी को लगाकर और डेरी का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके शुरू किया जा सकता है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि वंचितों के परिवार ने सूखे के दौरान 75–85ब आय दुग्ध उत्पादकों से प्राप्त की थी। इसने देश में बड़े स्तर पर देश में रोजगार को पैदा किया है।

यह क्षेत्र पूरे भारत में अधिक डेरी उद्यमियों का निर्माण कर सकता है, जो नए रोजगारों का सृजन करने के माध्यम से पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। वे शिक्षित बेरोजगार युवाओं, भारत में नौकरी के अभाव में गरीबी से जूझता हुआ सबसे बड़े वर्ग को नई नौकरियों का निर्माण करके भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के द्वारा बेहतर योगदान देने के योग्य बनाता है। यह गैर-परंपरागत संसाधनों के उपयोग में सुधार लाएगा, जैसे– सौर ऊर्जा, उत्पादों द्वारा कृषि, बारिश का पानी, जैविक खाद आदि। यह नए दुग्ध उत्पादकों का निर्माण करके नई तकनीकियों की मांग में सुधार कर रहा है। यह गरीबी के स्तर को कम करने, पोषित भूख को पूरा करने, आय और समानता को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। दूध के उत्पाद और पशुओं के निर्यात उन्मुखीकरण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों के विकास ने पशुओं में बीमारियों के उभरने, प्रजनन नीति के खतरों को कम किया है। इस प्रकार, भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि के साथ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि होगी।

दूध उत्पादन में सफलता लाभदुग्ध उत्पादन सफल कारोबार है। हमें केवल दूध उत्पादन के कारोबार को शुरू करने से नहीं बचने में अच्छे से जानता हो तो उसके द्वारा इसकी शुरुआत थोड़ी सी पूंजी लगाकर की जा सकती है, हालांकि इसे 100% सफल बनाने के लिए, एक व्यक्ति को भीड़ में दौड़ने और बंद आंखों के साथ अपना कारोबार शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति जो गंभीरता से इस व्यवसाय को शुरू

के डीडीसी को ताम्र पदक देने का प्रस्ताव किया गया है।

आकांक्षी ब्लॉकों में, तुलैल, सिंहपोरा, मंजगाम, केरन और ठकाराकोट ने पूर्ण संतुष्टि हासिल कर ली है। तीन अन्य मारवा, खाड़ी और इचेगोला ने पाँच संकेतकों में संतुष्टि हासिल कर ली है, जबकि ख्वास ने तीन में संतुष्टि हासिल कर ली है।

प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार भी दर्ज किया गया। इचेगोला (पुलवामा) ने अपने समग्र स्कोर में 9.13 अंकों का सुधार किया और मार्च 2025 में रैंक 2 पर पहुँच गया। तुलैल (बांदीपोरा) ने 6.66 अंकों की वृद्धि के साथ 68.90 अंकों के साथ रैंक 8 हासिल की।

इस अभियान ने 44 चिन्हित पिछड़े ब्लॉकों के लगभग 12.64 लाख लोगों (लगभग 10.3 प्रतिषत जनसंख्या) पर सकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली के बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई।

इन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए, संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में जिला विकास आयुक्तों, ब्लॉक-स्तरीय अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।

कृषि विशेष



करना चाहता है, तो उसे व्यापार शुरू करने से पहले अपनी आंखों को खोलने, पक्ष-विपक्ष का विश्लेषण करने, इस कारोबार के बारे में सबकुछ विस्तार से जानने और आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। यदि हम सही तरीके की रणनीति के साथ दुग्ध उत्पादन को शुरू करेंगे तो निश्चय ही हम इसमें बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे।

वर्तमान में बहुत सी प्रौद्योगिकियों और तकनीकी सहयोग की उपलब्धता है, जो हमारे डेरी व्यवसाय को सफल कारोबार बना सकती है। यह आजकल भारत में एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय है, जो अधिकतर भारतीय किसानों के साथ ही वाणिज्यिक व्यापारियों के रूप में चल रहा है। हमारे पास पूरी तरह से विकसित और प्रभावी ईआरपी सॉफ्टवेयर की किस्में हैं, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साथ सहयोग कर सकती हैं। हमारे पास अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र के राज्य को स्थापित करने की सभी सुविधाएं हैं। यह बहुत ही समय और भंडारण विशिष्ट व्यवसाय है, जो तत्काल परिणाम नहीं देता है, हालांकि समय के साथ ठोस परिणाम देता है। इस व्यवसाय के लिए बहुत अधिक धैर्य, समय और भरोसे की आवश्यकता होती है।

यदि आप इस व्यवसाय में वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कारोबार के मानदंड स्थापित करके उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप इस कारोबार में दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने और दूध उत्पादन व्यवसाय के उत्पादन के द्वारा सफलता को बनाए रख सकते हैं। दूध उत्पादन आर्थिक विकास के लिए अच्छा अवसर है, हालांकि किसी को इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए इसकी प्रक्रिया और व्यवसाय की प्रकृति को जानना आवश्यक है। यह वह व्यवसाय है, जो दूध, दही, घी, मट्ठा,

नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 में जम्मू-कश्मीर की धूम

नई दिल्ली 29 जुलाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिवर्तनकारी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्रतिष्ठित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद्र प्रधान के संबोधन से हुआ, जिन्होंने भारत में समावेशी और नवाचार-संचालित शिक्षा के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ओर से, शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ स्कूल शिक्षा सचिव जम्मू-कश्मीर राम निवास शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर डॉ. जी. एन. इतू, एसपीडी समग्र शिक्षा और एवएसएसए पहलु कुलगाम, जम्मू-कश्मीर से इन्spायर मानक पुरस्कार के दो ट्यूटी टॉपर छात्र भी मौजूद थे।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया के



साथ बातचीत में, कई अभिभावकों ने सभी हितधारकों के बीच, विशेष रूप से जमीनी स्तर की पहल के माध्यम से, एनईपी 2020 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में, सकीना इतू ने जम्मू-कश्मीर भर में आयोजित फ़एनईपी मेला-पैगामफ़ में



व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उच्च अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल ने एनईपी 2020 के संदेश को छात्रों, शिक्षकों और व्यापक समुदायों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है।

जम्मू-कश्मीर के स्कूली शिक्षा सचिव राम निवास शर्मा ने केंद्र

निर्धारित करने की आवश्यकता है। ऐसा करना, आपको सही रास्ते पर अपने व्यापार को चलाने में मदद करने के साथ ही असफलता के ऊपर सफलता के अवसर में वृद्धि करता है। दूध उत्पादन कोई आसान क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यह लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पादकों के व्यापार से संबंधित होता है। लोगों और खाद्यान्न उद्योग की ऊंची उम्मीदों के लिए दुग्ध उत्पादक व्यापारी के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य कच्चे दूध और दूध उत्पादकों की सुरक्षा और गुणवत्ता होना चाहिए। अनुकूल दशाओं के अंतर्गत अच्छी स्वास्थ्य दशाओं के सहित स्वस्थ पशुओं से स्वास्थ्यवर्धक दूध प्राप्त करने की निश्चितता होनी चाहिए।

वे लोग जो इस व्यवसाय में कार्यरत हैं, वे एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रबंध प्रणाली के भी हिस्से होने चाहिए। अच्छी कृषि प्रणाली, स्वास्थ्य और पशुपालन प्रथाओं का पालन करने की आवश्यकता है। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए इनकी देखभाल पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय को शुरू करने से पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना, प्रबंध के लिए आवश्यक सभी क्षेत्रों को घेरने में व्यापारी की मदद करते हैं।

► ***दूध उत्पादन के व्यापार के लिए ध्यान देने वाले कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं***

- * बुनियादी ढांचा
- * पशु प्रजातियां
- * पशुओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा
- * दूध निकालते समय स्वच्छता
- * पशुओं के चारे व पानी की व्यवस्था
- * पशु कल्याण और अनुकूलतम वातावरण
- * कुशल और ज्ञान रखने वाले कर्मचारी
- * पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए

प्रभावी नियंत्रक उपाय

- * कुल व्यय और लाभ
- * उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए
- * प्रभावी नियंत्रक बिन्दु
- * व्यापार की योजना के लिए पशुओं के

अनुकूल संरचना और स्थान
व्यापार को शुरू करने से पहले, किसी को भी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में मदद प्राप्त करने और पशुओं के लिए अच्छे खावादर रखने की जगह के लिए व्यापार के अनुकूल संरचना की योजना बनानी चाहिए। व्यवसाय की योजना बनाने समय पेशेवर विशेषज्ञों और एकाउंटेंट की सलाह लेना बेहतर है। यह व्यापार में सभी चुनौतियों को पूर करने के लिए लचीला होना चाहिए।

शासित प्रदेश में एनईपी 2020 के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षा में गुणवत्ता, समावेशिता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

समागम में शामिल हुए कश्मीर स्कूल शिक्षा निदेशक डॉ. जी. एन. इतू ने नई दिल्ली से कश्मीर में एनईपी मेला 2025 के आयोजन की बारीकी से निगरानी की। मीडिया से बात करते हुए, डॉ. इतू ने कहा, फ़एनईपी 2020 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जम्मू और कश्मीर में ‘पैगाम’ शीर्षक से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकेले कश्मीर घाटी में, लगभग 400 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 42,000 से अधिक छात्रों, 3,000 से अधिक शिक्षकों और संस्थानों के प्रमुखों के साथ-साथ बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।

भेड़पालन विभाग, कश्मीर ने पैरा-पशु चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन किया

श्रीनगर 29 जुलाई। भेड़पालन विभाग, कश्मीर ने अखिल जम्मू-कश्मीर भेड़ एवं ऊन श्रमिक संघ के सहयोग से लाल मंडी में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें विभाग में पैरा-पशु चिकित्सा पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहकारिता एवं चुनाव मंत्री जावीद अहमद डार ने की, जबकि सोनावाड़ी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने भी पैरा-वेटेनरी स्टाफ के समर्पण की सराहना की और जमीनी स्तर पर प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।

सोमिनार के दौरान, मंत्री ने विभाग के क्षेत्रीय कार्यों को सुदृढ़ करने और किसानों को सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए कश्मीर सभाग के जिलों में तैनात किए जाने वाले आठ नए पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाई।

सोमिनार में भेड़ पालन निदेशक कश्मीर डॉ. रफ़ीक अहमद शाह, कृषि निदेशक कश्मीर सरताज अहमद शाह, संयुक्त निदेशक (फ़र्म) डॉ. अजय सूदन, और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पैरा-वेटेनरी स्टाफ और अधिकारियों ने भी भाग लिया।